

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/1901

दिनांक : 26-02-18

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा।

विषय :-

Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्र संख्या एफ ()उवसं/तक/2018/1529
दिनांक 15.02.2018

विषयान्तर्गत लेख है कि आपने पत्रांक 1937 दिनांक 23.02.2018 द्वारा कृषि उपज मण्डल समिति द्वारा एन.एच.-76 बाई पास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी 96 हैक्टर वनभूमि के बारे में मौके की स्थिति से संबंधित 2 बिन्दुओं पर आपकी टिप्पणी प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है।

निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान पुनः आकृषित है:-

1. पूर्व में आपने पत्रांक 9317-18 दिनांक 25.08.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में इसक्षेत्र में 4000 पौधे लगाये है तथा इस क्षेत्र की भूमि को प्रत्यावर्तन करने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन होता है।
2. पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5654 दिनांक 10.07.96 (प्रति संलग्न) द्वारा इस वनक्षेत्र की 47 है0 भूमि पर अतिक्रमण होने की सूचना पत्र द्वारा दी गयी थी तथा अतिक्रमित क्षेत्र को मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र की अनुपालना में गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

उक्त वस्तुस्थिति के क्रम में लेख है कि उपरोक्तानुसार विरोधाभाष होने पर भी इस वनभूमि को प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव अग्रेषित करने से पूर्व आप द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की जांच नही कर प्रस्ताव को जल्द बाजी में अग्रेषित किया है। वनक्षेत्र की अनदेखी करने की दशा में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कारित होने की स्थिति का संदेह है। उप वन संरक्षक वनभूमि का कस्टोडियन है। अतः आप प्रस्तावित भूमि की सूक्ष्म रूप से जांच कर site inspection report तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें अन्यथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ. न. F.No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। अतः कृपया स्थिति स्पष्ट करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एवं मूल प्रस्ताव-4 सेट।

(Handwritten signature)

(इन्द्राज सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा

23

ओर से :-

वन संरक्षक, पूर्ववृत्ता,
कोटा ।

निमित्त :-

मंडल वन अधिकारी,
कोटा ।

क्रमांक :- एफ। 93/ए। 78/लेनो/वारी/ 5654

दिनांक :- 10/7/86

विषय :- रीसी द्वारा 47 है० वनभूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत आर्ये संदि 10331-32/24. 7. 93 के उपलोकन में विदित होता है कि रीसी द्वारा पूर्व में उन्हीं हेतुान्तरित 123 है० वनभूमि के अज्ञात इतले ली 47 है० वनभूमि में अतिक्रमण कर लिया है । अतः अवगत करावें कि उक्त अतिक्रमण को रोक्ने हेतु आप द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

वनभूमि पर इस प्रकार अतिक्रमण कर लेना अवैध ही संघीर बात है अतः आप द्वारा अतिक्रमण रोक्ने के विषय राजस्थान वन अधिनियम सू-राजस्थ अधिनियम तथा वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही पर जनसूचि की सुझावें ।

महोदय,

वन संरक्षक, पूर्ववृत्ता,
कोटा ।

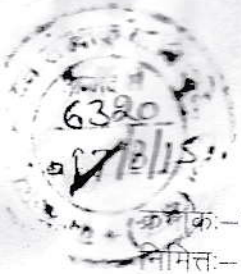
क्रमांक :- एफ। 96/96/लेनो/वारी/ 5655-56

दिनांक :- 10/7/86

प्रतिनिधि :- श्री वानु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

प्रतिनिधि :- दखिन्त वैश्व प्रबंधक, रीसी विनिर्दिष्ट कोटा की प्रेषित कर लेव है कि आप द्वारा अतिक्रमण 47 है० वनभूमि पर अवगत की सुझावें कर इन कार्यवाही की सुझावें ।

वन संरक्षक, पूर्ववृत्ता,
कोटा ।



॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ॥

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@gmail.com)

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2015-16/

दिनांक:

निमित्त:-

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(एफ.सी.ए.)
राज. जयपुर

FeA

8
26/8/15

विषय:-कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) कोटा के विस्तार हेतु दक्षिण दिशा की ओर हाइवे के नजदीक वन विभाग की भूमि में से 74 है. वन भूमि को आवंटन करवाने हेतु घोषणा में शामिल करवाने बाबत।

संदर्भ:-श्रीमान से आज दिनांक 25.08.2015 को दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में।

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि, कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) कोटा के विस्तार हेतु दक्षिण दिशा में 74 है 0 वन भूमि चाही गई है। जो कि, पथरीली एवं वृक्षहीन है।

निवेदन है कि, एन.एच.-76 सेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण में कोटा जिले की 111.637 है. वनभूमि (95.048 है. वन मण्डल कोटा के एवं 16.589 नेशनल घडियाल कोटा) का प्रत्यावर्तन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली के पत्रांक एफ नं: 8-13-2006-एफ.सी. दिनांक 06.07.2007 द्वारा किया गया था, जिसमें अधिरोपित शर्त संख्या 5 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2006 की पालना में कोटा बाई पास के दोनो तरफ हरित पट्टी वृक्षारोपण किया जाना है। उक्त वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2015-16 में आरंभ कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार कृषि मंडी विस्तार हेतु चाही गई वनभूमि कोटा बाई पास एवं कृषि उपज मंडी के मध्य में स्थित है, जिसमें शर्तानुसार हरित पट्टी वृक्षारोपण किया जाना है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 4000 पौधे लगा दिये गये है।

अतः निवेदन है कि, उक्त वनभूमि को कृषि उपज मंडी के विस्तार हेतु दिये जाने नें भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली के पत्रांक एफ नं. 8-13-2006-एफ.सी. दिनांक 06.07.2007 की अधिरोपित शर्तों की पालना का उल्लंघन होगा। रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

EO
(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2015-16/ 9318

प्रतिनिधि सभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक: 25-8-15

(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

F. No. 11-42/2017 - FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryaravan Bhawan,
Aliganj, Jorbhagh Road,
New Delhi - 110003

Dated: 21st January, 2018

To

The Principal Secretary (forests)
All States/Union Territory Governments

Sub: Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed -regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980.

Sir,

I am directed to invite your kind attention that the Forest Advisory Committee (FAC), constituted under Section 3 of the Forest Conservation Act 1980, while discussing proposals submitted under FC Act 1980, in its meeting held on 25.04.2017 noted with great concern somewhat inconsistent approach adopted by different Regional Empowered Committees of MoEF&CC and FAC itself in case of violations committed by user agencies of forest land in contravention of the provisions of Forest Conservation Act, 1980 and consequently recommending monitory penalty such as penal CA and penal NPV etc. in addition to mandatory compensatory levies. It was observed that the decisions to classify certain activities undertaken by the user agencies as violation and quantum of penalty imposed therein for the similar offence are different on different occasions due to absence of common guidelines.

2. It was, therefore, decided by the FAC to constitute a Committee of APCCF (central) Regional Offices, MoEF&CC and a member of the FAC to examine various aspects and different situations and activities which will constitute violations of provisions rules and guidelines issued under Forest Conservation act 1980 and suggest penalty in various situations, if the activities are treated as violation and thus as offence so as to dissuade the user agencies from committing such violations in future and compensate the loss caused due to such violation.

3. Accordingly on the recommendation of FAC, the following Committee was constituted vide this Ministry's letter of even number dated 05.06.2017.

- | | |
|---|----------|
| i. Dr. Tejinder Singh, APCCF, Regional Office, Bhopal; | Chairman |
| ii. Dr. Sanjay Deshmukh, Member, FAC; | Member |
| iii. Sh. Kanwarjit Singh, APCCF, Regional Office, Nagpur; | Member |
| iv. Sh. MRG Reddy, APCCF, Regional Office, Chennai; | Member |

4. The Committee submitted its recommendations to the Ministry on 15.05.2017 and the same was discussed in the Ministry and the final recommendation of the Committee was placed before the Forest Advisory Committee in its meeting dated 26.10.2017. The recommendation of the Committee was accepted and recommended by the FAC. The recommendations of FAC was placed before the competent authority in the Ministry. The

S. Deel

29.1.18

competent authority has accepted the report of the Committee on the recommendation of the FAC.

3. Accordingly, this Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:

A. In cases where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC:

- i. Diversion of forest land for non-forestry purposes without the prior approval of the competent authority in the state will be dealt under the provisions of Indian Forest Act 1927 or State Forest Acts or any other State act dealing with such land as the case may be. The land in question will not be considered as diverted under FCA 1980 and the status of land shall continue to be Forest.
- ii. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes have been granted by the state authority without the prior approval of the central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing the diversion. A report with full details of violation shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF & CC.

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

- i. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to **five (5) times the NPV** plus 12 percent simple interest till the deposits is made.
- ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.
- iii. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
- iv. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.

C. Violation /non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act:

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time:

- i. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.
 - ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.
- .00.03

D. Violation on account of change of land use in the approved mining plan:

- i. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.
- ii. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.
- iii. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para D(ii).

E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

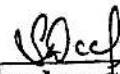


(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines/Coal/Steel/Power, Government of India.
3. Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
4. Nodal Officers, the Forest (Conservation) Act, 1980 All States/UTs.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, New Delhi.
7. PS to Hon'ble Minister of Environment, Forests and Climate Change and Minister of State for Environment, Forests and Climate Change.
8. Chairman, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs.
9. Member Secretary, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs
10. All Directors/Assistant Inspector General of Forest in Forest Conservation Division of MoEF&CC.
11. All Advisors/Directors/Dy Directors in Impact Assessment Division of MoEF&CC.
12. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
13. PPS to the Secretary for Environment, Forests and Climate Change, New Delhi.
14. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF&CC, Gol.
15. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, Gol.
16. PPS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, Gol.
17. Guard File.



(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests